

categories, including industrial units; and

(c) if so, the steps Government have taken to ensure continuous availability of diesel at all the diesel retail outlets in the districts?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Restrictions on the distribution of High Speed Diesel (HSD) oil have, by and large, been removed, while such restrictions continue to remain in force in the case of kerosene.

(b) No, Sir.

(c) The availability of HSD and inventory in depots is good and the demand of the product is now being fully met by the oil companies.

मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन विद्युत् परियोजना

2245. श्री एन. के. शेजवलकर : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन समय मध्य प्रदेश में कितनी विद्युत् परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और

इन्हें पूरा करने के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है और इस बारे में परियोजनावार स्थिति क्या है ;

(ख) 1980-81 में इन परियोजनाओं पर कितना काम हुआ है और इनके कब तक पूरा होने की संभावना है ; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं की संख्या क्या है जिन्हें मंजूर किया जा चुका है लेकिन जिन पर अभी तक निर्माण कार्य शुरु नहीं किया गया है और विशेष रूप से राज्यवार नहर परियोजना इस समय किस स्थिति में है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही तथा विद्युत् तथा जल विद्युत् परियोजनाएं और इनके पूरा होने की संभावित तारीख और अनुमानित लागत नीचे दी गई सारणी में दिखाई गई है :—

क्रम संख्या	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	पूरा होने की संभावित तारीख	अनुमानित लागत	मूल्य (लाख संशोधित रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
1	सापुड़ा विस्तार				
	यूनिट-8	210	9/82	12968	16558
	यूनिट-9	210	3/83		
2	कोरवा पश्चिम चरण-1				
	यूनिट-1	210	10/82	15599	20400
	यूनिट-2	210	4/83		

1	2	3	4	5	6
3	कोरवा पश्चिम विस्तार				
	यूनिट-3	210	12/83}	12994	17295
	यूनिट-4	210	6/83}		
4	बीर सिंह पुर				
	यूनिट-1	210	12/85}	20032	21000
	यूनिट-2	210	6/86}		
5	कोरवा सुपर ताप विद्युत केन्द्र (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम)				
	यूनिट-1	210	1/83}		
	यूनिट-2	210	7/83}	45080	53097
	यूनिट-3	210	1/84}		
	यूनिट-4	500	1986-87}		
6	पंच जल विद्युत परियोजना	2×80	1983-84	2828	8208
7	बोध घाट जल विद्युत परिोजना	4×125	1986-87	20930	*परियोजना को 1979 में स्वीकृति दी गई थी।

परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:

सदुड़ा विस्तार यूनिट--8 और 9:

दोनों यूनिटों के वायलर उत्पादन का कार्य प्रगति पर है। 1980-81 के दौरान यूनिट-8 के वायलर का उत्पादन कार्य लगभग 41 प्रतिशत तथा यूनिट 9 का लगभग 26 प्रतिशत उत्पादन कार्य पूरा हो गया था। यूनिट-8 के टर्बो जेनरेटर का उत्पादन कार्य जनवरी, 1981 में शुरू किया गया था।

2. कोरवा पश्चिम चरण-1 यूनिट 1 और 2:

दोनों यूनिटों के वायलर उत्पादन का कार्य प्रगति पर है तथा यूनिट-1

का वायलर ड्रम सितम्बर, 1980 में चढ़ाया गया था।

3. कोरवा पश्चिम विस्तार यूनिट 3 और 4:

इस स्कीम के सिविल कार्य, चरण-1 के सिविल कार्यों के साथ-साथ प्रगति पर थे। आनुवंशिक उपस्कर के आर्डर भी चरण-1 के साथ ही दे दिए गये हैं।

4. बीर सिंहपुर यूनिट-1 और 2:

वायलरों के लिए ए० बी० बी० को तथा टर्बो जेनरेटर के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को आर्डर दे दिए गये हैं।

5. कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र :

यूनिट-1 और 2 के बायलर उत्पादन का कार्य प्रगति पर है।

6. पेच जल विद्युत् परियोजना :

सभी सिविल कार्य प्रगति पर हैं इनटेक संरचना का निर्माण कार्य अग्रिम चरणों में है। प्रेशर शाफ्ट के लाइनिंग का कार्य प्रगति पर है। पट्टेच सुरंग पूरी हो चुकी है तथा बिजली घर केबन का खुदाई का कार्य भी पूरा होने के निकट है। टेल रेस की खुदाई का कार्य भी पूरा होने के निकट है।

7. बोध घाट जल विद्युत् परियोजना :

अवसरचकारमक कार्य प्रगति पर है।

(ग) ऐसी कोई भी स्वीकृत परियोजना नहीं है जिस पर कार्य शुरू न किया गया हो। जहाँ तक राजघाट नहर परियोजना से विद्युत् उत्पादन करने का सम्बन्ध है, मध्य प्रदेश सरकार से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण में इसकी जांच की जाएगी।

Proposal for liquidating Foreign Equity by M/s May and Baker

2246. SHRI KUSUM KRISHNA MURTHY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government could have saved foreign exchange worth Rs. 100 million if the proposal of liquidating foreign equity and associating Indian capital initiated by M/s. May & Baker was implemented in 1964-65 itself;

(b) whether the proposal of May & Baker was on the basis of assurance given by the company while securing some benefits from Government;

(c) whether the relevant file is missing for a long time and if so, how, who is responsible for this; and

(d) what action Government propose to take in this regard in view of the recommendation of the Foreign Agreements Committee 1965 for liquidation of equity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI DALBIR SINGH): (a) The details of the proposal of liquidating foreign equity and associating Indian capital initiated by M/s. May & Baker in 1964 have already been given in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 3193 answered on 13-3-1979. In regard to any possible excess repatriation abroad by the firm, it is not feasible to work out any figures, which can only be hypothetical, since the terms like payment of royalty, technical know-how fee and goodwill were yet to be sorted out subsequently as per the decision of the Foreign Agreements committee and were subject to acceptance by the company.

(b) whether any assurance was given by M/s. May & Baker is not verifiable at this distance of time.

(c) The concerned file was found to be missing. In spite of best efforts, the file could not be traced. An enquiry was held and Central Bureau of Investigation was requested to investigate the case. However, the Central Bureau of Investigation declined to undertake the investigation on the ground that they investigate only those cases where criminal intention was suspected. The Central Bureau of Investigation also stated that from the background of the case, it appeared that no misconduct on the part of officers was suspected, and hence no further investigation was initiated.

(d) The decision of the Foreign Agreements Committee taken in 1965 was not communicated to the company. While some terms were subject to negotiations, which would have naturally taken time, the Foreign Agreements Committee had suggested a period of 8 years for dilu-